

## 5. विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2024-2025 तथा 2025-2026 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता और मूलधन की पुनः चुकौती तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों का व्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्रम. सं.	विवरण	वास्तविक 2023-24	बजट अनुमान 2024-25	संशोधित अनुमान 2024-25	बजट अनुमान 2025-26
			(₹ करोड़ में)		
1	विदेशी ऋण	120429.20	93353.81	107711.53	111013.36
2	घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	-17990.81	-21491.12	-20034.00	-22134.53
3	निवल विदेशी ऋण (1+2)	<b>102438.39</b>	<b>71862.69</b>	<b>87677.53</b>	<b>88878.83</b>
4	नकद अनुदान	801.43	1038.81	1125.76	1124.53
5	वस्तु अनुदान सहायता	211.31	5.00	50.00	50.00
6	जोड़ (3+4+5)	<b>103451.13</b>	<b>72906.50</b>	<b>88853.29</b>	<b>90053.36</b>
7	ऋणों की चुकौती	-47317.13	-55910.40	-55685.20	-65388.45
8	विदेशी सहायता (ऋण की चुकौती को घटाकर) (6+7)	<b>56134.00</b>	<b>16996.10</b>	<b>33168.09</b>	<b>24664.91</b>
9	विदेशी ऋणों पर ब्याज अदायगी	29616.74	32597.90	34249.80	37120.17
10	विदेशी सहायता (चुकौती और ब्याज भुगतान को घटाकर) (8-9)	<b>26517.26</b>	<b>-15601.80</b>	<b>-1081.71</b>	<b>-12455.26</b>

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

### (क) बहुपक्षीय स्रोत

#### 1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

### (क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक स्रोतों की तुलना में अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- राष्ट्रीय गंगा नदी परियोजना, तमिलनाडु संधारणीय शहरी विकास परियोजना, क्षय रोग (टी.बी.) उन्मूलन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मुख्य सड़क नेटवर्क विकास परियोजना, गुजरात त्वरित ज्ञानार्जन के परिणाम (गोल) कार्यक्रम।

### (ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के दायरे से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिंगेशन, औद्योगिक मूल्य वर्द्धन प्रचालन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण आदि।

## 2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी वर्ष 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए वर्ष 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन विद्युत, परिवहन, शहरी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थागत संधारणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास आदि तक फैले हैं। सरकार की तरफ से एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं: विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, 'मध्य प्रदेश जिला सड़क II क्षेत्र परियोजना', कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार III परियोजना, मध्यप्रदेश सिचाई क्षमता सुधार परियोजना, महाराष्ट्र ग्रामीण हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली विस्तार कार्यक्रम और दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली निवेश परियोजना-1 आदि।

## 3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूँजी निवेश हेतु वित पोषण के लिए रोम संधि के तहत वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैं: बैंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना-ए।

## 4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा बारह चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

एनडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की मुख्य जिला सड़कों का विकास एवं उन्नयन, मध्यप्रदेश बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, मध्य प्रदेश मुख्य जिला सड़क II परियोजना, असम पुल परियोजना और मणिपुर जलापूर्ति परियोजना, आदि।

## 5. एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)

एशिया अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए क्रृति देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:- बैंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6, आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना और आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3, आदि।

## 6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशेष एजेन्सी के रूप में वर्ष 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने वर्ष 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित प्रवर्षण के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें पूर्वतर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वतर-नागालैंड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वर्तमान में चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं: छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना, महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास परियोजना आदि।

## 7. वैशिक निधि संगठन

यह वैशिक निधि एडस, टी.बी और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वितपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एडस, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैशिक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही तीन परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैशिक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एडस नियंत्रण परियोजना, 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सहायता और उपचार', 'गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'टी.बी' हैं।

## (ख) द्विपक्षीय स्रोत

### 1. जापान

जापान वर्ष 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण और स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- अहमदाबाद मेट्रो परियोजना (I), पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (चरण-I)(I), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट (II) और मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना (II) आदि।

### 2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग, संधारणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू की सहायता से चलने वाली कुछ प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैं- गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु सहिष्णुता पुनर्निर्माण चरण-II, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु अनुकूल पुनर्निर्माण चरण-I, मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए समेकित और हरित शहरी आवागमन, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में बस सेवाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण-IV, संधारणीय शहरी अवसंरचना विकास-चेन्नै तूफान-जल प्रबन्धन, आदि।

### 3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में अनुपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (यूनिट 5 और 6) के निर्माण के लिए करार दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल सं.2 पर जुलाई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

### 4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता प्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एएफडी द्वारा वित्तोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं।

एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- नागपुर मेट्रो के लिए ऋण सुविधा करार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और सूरत मेट्रो आदि।

### 5. कोरिया गणराज्य

दक्षिण कोरिया सरकार और भारत सरकार ने नागपुर-मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रैसवे की आई टी एस स्थापना परियोजना और बहु-मॉडल और समेकित लॉजेस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम (स्माइल) के सुदृढ़ीकरण के लिए दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।